श्री मोरारजी देसाई : क्या चल रहा है, वह मुझे पता नहीं है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ क्या यह दुरुस्त नहीं है कि 31 मार्च, 1968 तक पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में 3046 करोड़ रुपये से जायदा इन्वेस्टमेन्ट की जा चुकी है मगर इस इन्वेस्टमेन्ट का जितना अच्छा परिणाम निकलना चाहिये, वह नहीं निकला और क्या यह भी दुरुस्त नहीं है कि सरकार ने पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को कामियाब करने के लिये जिन ठोस एकदामात की जरूरत महसूस भी की वह भी कभी नहीं उठाये जा सके ?

जैसा कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने 14-15 जून, 1967 को तमाम पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के हेड्ज़ की बैठक बुलाई थी और उसमें कहा गया था कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में 30 फीसदी स्टाफ ज्यादा है और नार्मज़ फिक्स होने चाहिये जबकि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का प्रोजेक्ट एस्टीमेट आज तक पास नहीं किया गया और वह प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में भी आ चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार कौन से ऐसे एकदामात कर रही है या करना चाहती है जिससे पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की सफलता में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : पहले सवाल के जवाब में जो मैं ने कहा, वही इस सवाल पर भी लागू होता है।

श्री बेणी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज का सवाल है उसमें हम देखते हैं कि घाटा ही घाटा होता आ रहा है। मैं माननीए वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे कोई ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, जैसे लड़ाई होने पर हम कांस्क्रिप्शन करते हैं, उसी प्रकार वे सफल व्यापारियों का कांस्क्रिप्शन करें और उन्हें इन अन्डरटेकिंग्ज में लगायें ताकि उनको सफलता पूर्वक चलाया जा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो एक सूचना है, मगर अजीब सी है।

SHRI S. R. DAMANI : The main reason for the uneconomic working of the public sector undertakings. as pointed out by the Committee on Public Undertakings is surplus staff, excess workers and low productivity. In view of this, may I know whether any concrete decision has been taken so far and whether the State Governments are co-operating with us in improving the working of the public sector undertakings ?

SHRI MORARJI DESAI : As I have said, decisions are being taken and they will soon be taken, and when they are taken I shall be in a position to say exactly what steps are taken.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की अभी फिलहाल जो रिपोर्ट निकली है उससे मालूम होता है कि वहां पर आइडिल कैपेसिटी इस हद तक है कि 1971 तक वहां कुछ नहीं होने वाला है, तो इस के बारे में मन्त्री महोदय ने क्या सोचा है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका भी सोचा जा रहा है।

मनीला में एशियाई विकास बैंक की बैठक

+

1499. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवेन सेन :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री मधुकर सूपकार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चित्त बासु :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी:

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968

के प्रथम सप्ताह में मनीला में एशियाई विकास बैंक की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था और उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक की कार्यसूची में, बैंक की 1967 की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, 1967 और 1968 के प्रशासनिक बजटों की समीक्षा करना, वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और बैंक के कामकाज के नियमों और विनियमों की तथा बैंक के क्रिया-कलाप की समीक्षा करना शामिल था।

कार्यसूची की विभिन्न मदों पर विचार करने के बाद गवर्नरों के बोर्ड ने एशियाई विकास बैंक द्वारा अपने प्रथम वर्ष में किये गये कार्य के प्रति सन्तोष प्रकट किया।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमान्, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह बैंक क्या केवल व्यापारिक उद्देश्यों के लिये ऋण देगी या विकास प्रयोजनाओं के लिये भी ऋण देगी और इस वर्ष में, जिस वर्ष की रिपोर्ट आई है, कितने देशों ने ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उनका किस प्रकार निपटारा किया गया ?

श्री मोरारजी देसाई : अभी तो उसकी शुरुआत ही हुई है, एक साल हुआ है। अभी सिर्फ थाईलैण्ड के लिये मंजूर किया है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : प्रार्थना-पत्र कितने आए ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रार्थना-पत्र शायद दो-तीन आये वैसे मैं एकदम से नहीं कह सकता कि कितने खास आये।

दूसरी बात उन्होंने यह की है कि एशी-कल्चरल प्रास्पेक्ट्स में क्या परिस्थिति है, उसका संशोधन किया है और यह चल रहा है। इस तरीके से वह कार्य शुरू कर रहे हैं और जितना काम किया है वह एक साल में पूरा किया है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमान, इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि यू० एस० ए०, कैनेडा और नीदरलैण्ड और जापान आदि देश जो प्रायः इसके मेम्बर भी नहीं हैं, उन्होंने बहुत आसान शर्तों पर इस बैंक को धन देने का वचन दिया है और इस तरह के आफर्स दिये हैं, ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ऋणदाता देश किस ब्याज दर पर बैंक को रुपया देंगे और ऋणार्थी देशों को किस ब्याज पर ऋण दिया जायेगा और इस मामले में ऋण-दाता और ऋणार्थी देशों की ब्याजदर में कोई संतुलन रखने का विचार किया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : पहले तो जिन लोगों ने मदद करने का वायदा किया है; वे सब मेम्बर हैं इसके। इसमें सिर्फ एशियाई लोग ही नहीं, जो लोग भी आ सकते हैं, जिनको मेम्बर होना है, सब मेम्बर होते हैं मगर खर्चा सिर्फ एशियाई रीजन में करना है। यह इसका मतबल है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आ जायं क्योंकि धन तो इन लोगों के ही पास है, ये आ जायं, तभी फायदा होता है। इन लोगों ने जो मदद करने के लिये कहा है उसकी सारी शर्तें तय नहीं की गई हैं। हम उसमें कहते हैं कि ऐसी शर्तें होनी चाहिये जिससे विकास करने वाले देशों को मदद पहुँचे न कि उनके ऊपर बोझा पड़ जाये। उसके ऊपर बात-चीत चल रही है।

दूसरी बात हम यह भी कर रहे हैं कि इसमें बन्धन नहीं होना चाहिये कि जिस देश ने मदद की उसी देश में से सामान की खरीद की जाये। ये सारी बातें चल रही हैं, जब फैसला होगा तभी मालूम हो सकेगा।

श्री देवी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूँ ऐशियन डेवलपमैंट

बैंक में अमेरिका और जापान के दो दो सौ मिलियन डालर के शेयर हैं तथा भारतवर्ष के करीब करीब 93 मिलियन डालर के ऐसी अवस्था में भारत ऐशियन डेवलपमैंट बैंक का तीसरा बड़ा हिस्सेदार होता है। चूंकि अमेरिका और जापान विकसित देश हैं वे इस बैंक से किसी प्रकार का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं, भारतवर्ष ही पहला देश है जिसे इस बैंक से अपने विकास कार्यों के लिये अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिए। इस अवस्था में क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज तक ऐशियन डेवलपमैंट बैंक से भारतवर्ष को कितनी और किस प्रकार की सहायता मिली है तथा अन्य देशों को कितनी मिली है तथा आगामी पंचवर्षीय योजना में वे इस बैंक से कैसी और कितनी सहायता की आशा करते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : जितने शेयरहोल्डर्स हैं उस में भारत का तीसरा नम्बर है। पहले जापान और अमरीका दोनों की 200 मिलियन डालर की शेयर होल्डिंग है जबकि हमारी 93 मिलियन डालर की है। अब इस में से आधा भर लिया जाता है पूरा नहीं लिया जाता है और वह भी पांच साल के अन्दर पूरा होगा। भारतवर्ष भी एक विकास करने वाला देश है वह विकसित देश नहीं है मगर इन सभी देशों में भारत बड़ा देश है और भारत इस में मदद करना चाहता है मदद लेने के बजाय। आज वह हमारा इरादा है आगे चल कर जरूरत पड़े हम मांगें दूसरी बात है मगर इस में हम ईर्ष्या पैदा नहीं करना चाहते हैं कि हम ही उस में जो सारा पैसा हो उसे ले जायं क्योंकि हमारा सब से बड़ा देश है और इसलिए मैं ने ऐसा वहां कहा था कि जब तक हमें खास जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक वहां से लेने का हम खयाल नहीं करेंगे। इस का मतलब यह नहीं है कि जरूरत पड़े तो हम लेंगे ही नहीं वह बात नहीं है मगर जहां तक बने हम नहीं लेना चाहते मदद करना चाहते हैं यह भी मैंने उन को कहा था।

श्री बेणी शंकर शर्मा : हमारा भारत देश एक भिक्षुक देश है...

श्री मोरारजी देसाई : आप भिक्षुक भले ही हों देश भिक्षुक नहीं है।

श्री मधु लिमये : यह व्यक्तिगत हमला अच्छा नहीं है। मैं भी एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा।

श्री मोरारजी देसाई : जरूर पूछिये। मैं भिक्षुक हो सकता हूँ लेकिन देश भिक्षुक नहीं हो सकता।

MR. SPEAKER : Shri Supakar.

SHRI UMANATH : Undergrounds talks are going on.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Of the many points made by the Deputy Prime Minister in the conference, the two main ones were the possibility of export promotion our country through this organisation stringless aid to under-developed countries. May I know how far he received some hopes of the prospects of these two hopes fructifying as a consequence of the deliberations of the conference ?

SHRI MORARJI DESAI : These hopes, we may hope, will fructify. One always lives in hopes. But I cannot say that they will fruitify to all the extent to which it is expected. But I am sure that they will fructify to a large extent.

SHRI D. C. SHARMA : I think the Deputy Prime Minister said just now that India stands third so far as the contributing nations are concerned. What amount has India contributed now, how much will she be contributing in the next five years and has any optimum been fixed for India's contribution after five or ten or fifteen years ?

SHRI MORARJI DESAI : The hon. Member understands Hindi. Still he may

have been inattentive. Therefore, he has not followed what I said before. I have said that $ 200 million each is the shareholding of America and Japan and $ 93 million is the shareholding of India. Out of this, half is to be called for and that too in five years, and half of that which we contribute will be in unconvertible currencies and the other half in convertible currencies.

SHRI S. S. KOTHARI : Have the developed countries imposed any restrictions while contributing to the share capital of the Bank ?

SHRI MORARJI DESAI : No Sir, But the question of restrictions on special Fund Contribution is under negotiation. But the present trend has been that those who give help expect that things should be purchased from those countries. It is because of that attraction that help is also given. But there are countries which also give without attaching that condition. Therefore, we are requesting all other countries to see that this kind of help must be given in a manner where there should be freedom to buy from all countries. But I cannot say that has been accepted yet.

SHRI UMANATH : The developed countries, among the countries holding shares in the Bank, control about 80 per cent or a substantial majority of the shares. I understand that voting rights have got everything to do with the holding of shares also. As we have seen in the UNCTAD recently, the conduct of developed countries was to find somehow methods and avenues of exploiting the developing countries. In view of this, what is the earthly purpose in our continuing in the Bank and offering ourselves to be either explotied or get a bad odour of their conduct ? Secondly, with regard to our share capital, the hon. Minister mentioned $ 93 million dollars. I understand that it is to be in foreign exchange. We are finding ourselves in difficulty in getting foreign exchange even for repayment of our loans. When that is our position, how is the Deputy Prime Minister going to find the foreign exchange for this purpose.

SHRI MORARJI DESAI : I do not agree with the inference the hon. Member has drawn about the UNCTAD, that the developed countries want to exploit the under-developed countries. I think it is a very unfair imputation...

SHRI UMANATH : It is most fair.

SHRI MORARJI DESAI : The hon. Member is seldom fair in these matters. Therefore, I am not surprised.

SHRI UMANATH : Fairest.

SHRI MORARJI DESAI : In these matters, he has only one attitude, that everybody else except he and his friends, is an exploiter. I cannot help it. Let him think like that ; it does not matter to me.

SHRI MADHU LIMAYE : He has no friends among developed countries.

SHRI MORARJI DESAI : Russia is there. It is developed. Therefore that is not correct.

As I was saying, this is not the proper attitude to take.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : उन के लिए रशिया भी ऐक्सप्लायटर है, सिर्फ चाइना नहीं है।

SHRI MORARJI DESAI : When it comes to that, they will support China, not us. Do not be under any delusion in these matters. They are all the same.

As I said, we are giving half convertible and half unconvertible currencies spread over five years. But if we want to have regional co-operation and as we are the biggest country, we have certainly to contribute ; we should contribute even more than the others ; we should contribute even more than America or Japan. But we have not the capacity to do so. Therefore, we are stretching ourselves a bit to help in this process because it is in the interest of everybody that we should do so.

SHRI UMANATH : Are we going to take a loan from America for the purpose of finding the foreign exchange for this contribution ?

SHRI MORARJI DESAI : Even if we take a loan from America, that should not bother my hon. friend. If he is bothered, let him prevail upon his friends to give us loans.

SHRI HEM BARUA : Is it a fact that representatives of the developed countries, particularly the representatives of Japan, attending this conference of the Asian Development Bank in Manila, have said that they are not prepared to channel monetary aid to developing countries through the Bank, and whatever attempt at channelling monetary aid to developing countries would have be done on the basis of bilateral agreements ? If so, what is the reaction of Government to this ?

SHRI MORARJI DESAI : I did not see any such statement myself.

SHRI HEM BARUA : I have read that.

SHRI MORARJI DESAI : There are both bilateral and multilateral aid. This is a method of having multilateral aid.

SHRI HEM BARUA : Representatives of some developed countries have said that they do not want to channel monetary aid to developing countries through this Bank.

SHRI MORARJI DESAI : If they had done so, they would not have become shareholders of the Bank.

All have not become shareholders, but there are several countries which have become shareholders. There are 19 members who are of the region ; there are 13 members who are out of the region which are, of course, only the developed countries. Of course, there are more developed countries also. But the developed countries who have joined have done so with the intention to help in this way and there cannot be any other intention than of helping in the process of development of this region.

SHRI RANGA : Are we to understand that this Bank has been brought into existence in order to help all these eastern countries to have trade as amongst themselves to a greater extent than it has been in the past when they were having trade more with the western nations and that in order to facilitate that trade this Bank is established to advance credit to such of the countries as would like to purchase things with credit advanced from this Bank from other Asian countries ? If that is so, then, we would certainly welcome the establishment as well as the functioning of this Bank. But has any invitation has been to Soviet Russia and other countries associated with her to come and join this Bank and advance credit in the same way as the other western advanced countries have been invited ?

SHRI MORARJI DESAI : Russia had taken part in the preliminary meeting before the establishment of this Bank when the ECAFE had called this meeting. But when the Bank was actually launched, Russia did not join. We should be happy if they join it, but if they do not join, we cannot force them to join.

SHRI RANGA : The invitation is still there ?

SHRI MORARJI DESAI : The invitation is open to all of them. That is there.

Central Government Health Service Scheme

*1503. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the status of the Central Government Health Service Scheme has not so for been fixed ;

(b) whether it is also a fact that the Central Government Health Service Scheme at Bombay has been declared as a Subordinate Service since its inception in 1963 ;

(c) whether it is further a fact that C.G.H.S. Scheme staff in Delhi and elsewhere has also been demanding that it should be declared as Subordinate Service ; and

(d) if so, what stands in the way of its being declared as Subordinate Service ?